

‘चढ़ावा चोरी’ को लेकर संसद में संग्राम

विपक्ष का भारी हंगामा, खड़गो बोले-ईडी कहा है
रिजिजू ने कहा-विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा



वित्त मंत्री सीतारमन ने शोर-शराबे के बीच बिल पेश किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही दिन में दो बार स्थगित हुई। 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के आधे घंटे के भीतर स्थगित भी हो गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट ही चल पाई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा- राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था।

दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। पीठासीन दिलीप सैकिया ने इन सांसदों को नारे न लगाने और बैठ जाने के लिए कहा लेकिन वे नहीं माने। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टैक्सेशन एंड अदर्स लॉ (संशोधन) बिल पेश किया। बिहार और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा कि अब साफ है कि जनता भाजपा से ऊब चुकी है।

यूपी विधानसभा में पोस्टर दिखाने पर जमकर बवाल

● सपा विधायक बाहर निकाले गए, सीएम का हमला

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी विधानमंडल में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सपा और कांग्रेस ने इसको लेकर सदन में नारेबाजी की। इस दौरान जैसे ही सीएम योगी बोलने के लिए खड़े हुए, सपा विधायक सचिन यादव ने हाथ में एक पोस्टर लहराया जिसमें सीएम की फोटो के साथ चढ़ावा चोरी को लेकर कई सवाल पूछे गए थे। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया। इस दौरान सपा की महिला विधायकों ने हंगामा किया।



चढ़ावा चोरी का साधु-संतों से कोई मतलब नहीं

सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो भी लोग पकड़े गए हैं, उनका भाजपा और साधु-संतों से कोई लेना देना नहीं। इसके बावजूद विपक्ष के नेता सनातन धर्म पर अनावश्यक लांछन लगा रहे हैं। ये लोग सत्य को दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग सदन में चर्चा से भागना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से जो एजेंडा हाउस द्वारा तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हों, उन सभी पर विरोधी दल के लोगो ने कोई रुचि नहीं ली।

बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद हलचल तेज



नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की मुलाकात हुई है। भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिश ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में पीएम से उनके चैंबर में मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। नीतिश ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। हालांकि, बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद यह मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और नीतिश कुमार ने एक दिन पहले जारी हुए पटना शहर की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजों पर भी चर्चा की। हालांकि, भाजपा या जदयू में किसी भी दल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

बकाया जमा कर डिफॉल्टर बने किसानों के लिए योजना

● कैबिनेट में पांच हजार किसानों को मिला कवच, बैंक से लोन, खाद बीज पा सकेंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान कल्याण को सर्वाधिक महत्व देते हुए सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दी, जिससे सहकारिता विभाग के लगभग 5 हजार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की कवच योजना को अनुमोदित किया। यह योजना सहकारी समितियों के ऐसे लगभग 5 हजार किसानों के लिए है, जिनके ऋण खाते में गड़बड़ियां हुई हैं और जांच में देरी की वजह से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।



किसानों की राशि हड़प गए बैंक मैनेजर

अब ऐसे किसानों को मुख्य धारा में लाकर योजना के तहत नया ऋण मिल सकेगा। निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ रुपये की सीमा तक की नीधि का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार भी किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूजी की सहायता एक बार उपलब्ध करायेंगी। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार के ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य रूप से सहकारिता से जुड़े लगभग 5 हजार किसानों, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, खेल अधोसंरचना के विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस के सशक्तिकरण और शैक्षणिक संवर्ग के हित संवर्धन पर केन्द्रित है। मंत्रि-परिषद की बैठक में आगामी वित्तीय वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।

तमिलनाडु के नेता विपक्ष उदयनिधि गिरफ्तार, फिर रिहा

● एक्ट्रेस तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, उस पर सुनवाई होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर आयोजित रैली में उदयनिधि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान भोड़ से तृषा, तृषा के नारे लगे। आरोप है कि इस



पर उन्होंने कहा, पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को डबल मीनिंग और महिलाओं का अपमान करने वाली बताया। इसी आरोप के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

डीएमके नेता बोले-उदयनिधि ने किसी का अपमान नहीं किया- डीएमके नेता टीकेएस इलांगोवन ने कहा कि मैंने पूरी स्पीच सुनी। जैसा कहा जा रहा है, भाषण में वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने (उदयनिधि) केवल सीएम की नाकामियां गिनाईं।

दतिया उपचुनाव में हार के बाद ऐक्शन मोड में भाजपा

● सीएम आवास में समीक्षा बैठक, पार्षदों पर कार्रवाई संभव ● परिणाम की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति की गई गठित

भोपाल। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को 6,016 वोटों से मिली हार के बाद पार्टी ने संगठनात्मक समीक्षा शुरू कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भोपाल स्थित आवास पर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी, मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में हार के कारणों, संगठन की भूमिका, भीतरघात की शिकायतों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, दतिया के कुछ पार्षदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राकेश शुक्ला समेत करीब दो दर्जन नेता मौजूद रहे। पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट में कुछ पार्षदों पर भितरघात के आरोप लगे हैं।

कोलकाता और भोपाल के लिए अब रीवा से मिलेगी सीधी फ्लाइट

● नौ अगस्त से शुरू हो जाएगी सेवा, विंध्य क्षेत्र में बढ़ेगी कनेक्टिविटी



भोपाल। विंध्य क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। अब रीवा एयरपोर्ट से भोपाल और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। नौ अगस्त से फ्लाइट की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली दौरे के दौरान डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की है। नौ अगस्त से रीवा-कोलकाता और रीवा-भोपाल के लिए 72 सीटर विमान की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है। साथ ही उनसे कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश में हवाई संपर्क का विस्तार हो रहा है। रीवा से कोलकाता एवं भोपाल के लिए शुरू होने वाली नई विमान सेवाएं विंध्य क्षेत्र में उद्योग, व्यापार बढ़ाएंगी।

इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग की फर्जी शादी कराने वाले मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। इंदौर पुलिस ने मानव तस्करी और नाबालिग बालिकाओं की फर्जी शादी कराने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य षड्यंत्रकर्ता सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई थाना बाणगंगा पुलिस ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले की जांच के दौरान की। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता की गरीबी और पारिवारिक मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अधिक पैसे कमाने और मकान खरीदने का लालच दिया। इसके बाद उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग दर्शाया गया और स्वयं को उसके परिजन बताकर रतलाम निवासी युवक से करीब 3 लाख रुपये में फर्जी शादी करा दी गई।

इसी दौरान पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई



अपहरण की रिपोर्ट पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की। पुलिस की सख्ती

से घबराकर आरोपी पीड़िता को वापस इंदौर छोड़ गए, जहां उसने पूरी घटना का खुलासा किया।

मामले में पुलिस ने संजू उर्फ संजय यादव, रामविलास उर्फ राकेश यादव, संजु पाटीदार तथा नंदराम पाटीदार को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि गिरोह पहले भी कई नाबालिग बालिकाओं की फर्जी शादी करार मानव तस्करी कर चुका है और इसका नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हो सकता है। पुलिस फर्जी दस्तावेज, अवैध लेन-देन और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। इंदौर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिग बालक-बालिकाओं को शादी, नौकरी या अधिक पैसे का लालच देकर बहलाने-फुसलाने का प्रयास करे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर समय रहते रोक लगाई जा सके।

प्रेम नगर स्थित टेंट गोदाम में लगी आग, निगम की तत्परता से टला बड़ा हादसा

नवल किशोर

सूचना मिलते ही दमकल वाहन पहुंचा मौके पर, फायर अमले ने त्वरित कार्रवाई कर आग पर पाया काबू

कटनी। नगर निगम की त्वरित आपदा प्रबंधन व्यवस्था और दमकल अमले की सतर्कता के चलते मंगलवार को किदवाई वार्ड के प्रेम नगर स्थित एक टेंट गोदाम में लगी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की तत्पर कार्रवाई से आग को आसपास के क्षेत्र में फैलने से रोकते हुए एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। मंगलवार 4 अगस्त 2026 को प्रातः 10:52 बजे नगर निगम कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना एनकेजे क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर स्थित एक टेंट गोदाम में आग लग गई है।

सूचना मिलते ही नगर निगम प्रशासन ने बिना किसी विलंब के बस स्टैंड जोन स्थित फायर स्टेशन से दमकल वाहन एवं प्रशिक्षित फायर अमले को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया। प्रभारी फायर इंचार्ज शैलेंद्र दुबे ने बताया कि दमकल दल ने मौके पर पहुंचते ही स्थिति का आकलन कर सुनियोजित ढंग से आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया। फायर कर्मियों ने पूरी मुस्तैदी, सूझबूझ और समन्वय के साथ कार्य करते हुए कुछ ही समय में आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। साथ ही आसपास रखे ज्वलनशील सामान और



समीपवर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करते हुए आग को फैलने से रोक दिया, जिससे जन-धन की संभावित बड़ी क्षति टल गई।

नगर निगम प्रशासन ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए फायर ब्रिगेड चौबीसों घंटे सतर्क रहती है। घटना के कारणों एवं हुए नुकसान का आकलन संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि आग, दुर्घटना अथवा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम या संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई कर जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश

नवल किशोर

कटनी। पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलेभर से पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सभी प्रकरणों का त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक एवं आपसी विवाद, साइबर ठगी, महिला संबंधी शिकायतों सहित विभिन्न मामलों के आवेदन प्राप्त हुए। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी, वीरेन्द्र धार्वे, उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा, उप पुलिस



अधीक्षक शिवा पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य विभागों से जुड़े मामलों में संबंधित विभागों से समन्वय कर शीघ्र समाधान कराने के भी निर्देश दिए गए।

महापौर जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं पर हुई सुनवाई, कई मामलों में मौके पर दिए गए निर्देश

नवल किशोर

कटनी। नगर पालिक निगम कटनी में मंगलवार 4 अगस्त को आयोजित महापौर जनसुनवाई में शहर के विभिन्न वार्डों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरि के समक्ष रखीं। जनसुनवाई के दौरान पेयजल, सड़क, नाली, स्वच्छता, अतिक्रमण, राजस्व एवं अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित आवेदनों पर विस्तार से सुनवाई की गई। महापौर ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रकरणवार जानकारी प्राप्त की तथा समयसीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि

नागरिकों की समस्याओं का समाधान केवल कागजों



तक सीमित न रहे, बल्कि उसका परिणाम भी समय पर दिखाई देना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

एक ही छत के नीचे मिला समाधान, विभागीय समन्वय रहा प्रभावी- जनसुनवाई में नगर निगम की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एक साथ उपस्थित रहे, जिससे आवेदकों की

शिकायतों पर तत्काल विभागीय समन्वय स्थापित हुआ। कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए, जबकि शेष प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। महापौर श्रीमती सूरि ने कहा कि जनसुनवाई नागरिकों और नगर निगम के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने शहरवासियों से प्रत्येक मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में शामिल होकर अपनी समस्याएं सीधे प्रस्तुत करने की अपील करते हुए कहा कि नगर निगम पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी प्रशासन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

हत्या के मामले में फरार तीसरा आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल

अतुल जैन

आम तोड़ने के विवाद में हुई थी महिला की हत्या, पहले ही दो आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार खनियाधाना। थाना खनियाधाना पुलिस ने हत्या के मामले में करीब ढाई माह से फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल पिछोर भेज दिया गया। इससे पहले इस मामले के दो अन्य आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर जिले में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामदास प्रजापति एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना खनियाधाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रकरण में फरार आरोपी राहुल प्रजापति को गिरफ्तार किया।

आम तोड़ने के विवाद ने लिया था खूनी रूप

पुलिस के मुताबिक, 19 मई 2026 को ग्राम अछरौनी निवासी फरियादिया श्रीमती खुमनिया प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने घर के बाहर बैठी थीं। इसी दौरान उनके देवर सिरनाम



प्रजापति, भतीजे राहुल प्रजापति तथा लुक्का उर्फ सोनसिंह प्रजापति वहां पहुंचे और खेत के साझे आम के पेड़ से आम तोड़ने की बात को लेकर विवाद करने लगे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान सिरनाम प्रजापति ने लाठी से हमला कर खुमनिया प्रजापति के सिर में गंभीर चोट पहुंचाई, जबकि राहुल प्रजापति और

लुक्का उर्फ सोनसिंह ने भी खुमनिया तथा रामकुमार प्रजापति के साथ मारपीट की। घटना के बाद थाना खनियाधाना में अपराध क्रमांक 177/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। उपचार के दौरान खुमनिया प्रजापति की ग्वालियर स्थित जेएचएच अस्पताल में मृत्यु हो जाने पर प्रकरण में हत्या सहित संबंधित धाराएं

बढ़ा दी गई।

रेड्डी चौराहे से दबोचा गया आरोपी

जांच के दौरान पुलिस ने पहले ही आरोपी सिरनाम प्रजापति और लुक्का उर्फ सोनसिंह प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीसरा आरोपी राहुल प्रजापति पुत्र सिरनाम प्रजापति (27) निवासी प्रजापति मोहल्ला, ग्राम अछरौनी, थाना खनियाधाना, लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे 3 अगस्त को रेड्डी चौराहे से गिरफ्तार किया। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय खनियाधाना में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट मिलने के बाद उसे उपजेल पिछोर भेज दिया गया।

इन पुलिसकर्मियों की रही सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक केदार सिंह यादव, उप निरीक्षक छाया राय, सहायक उप निरीक्षक रामसिंह भिलाला, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिंह पाल, प्रधान आरक्षक नीतू सिंह, प्रधान आरक्षक सोनू यादव, आरक्षक अनूप कुमार, आरक्षक अरविंद्र सिंह कौरव, आरक्षक संदीप तथा महिला आरक्षक हनीराजा चौहान की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

वन मंडल कटनी में 117 जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष सचिवों का प्रशिक्षण सम्पन्न

जैव विविधता संरक्षण, लोक जैव विविधता पंजी और लाभ-प्रभाग राशि के प्रभावी उपयोग पर दिया गया प्रशिक्षण

नवल किशोर

कटनी। सामान्य वन मंडल कटनी द्वारा आज जिले की 117 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के अध्यक्ष एवं सचिवों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समितियों को अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाते हुए स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को जनभागीदारी के माध्यम से मजबूत करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ वनमंडल अधिकारी श्री गर्वित गंगवार ने किया। उन्होंने कहा कि जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आधारशिला हैं। इनके माध्यम से ग्राम स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण, संवर्धन तथा पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। प्रशिक्षण में



मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड, भोपाल के तकनीकी विशेषज्ञ विवेक पाण्डेय एवं शुभम सिंह ने जैव विविधता प्रबंधन समितियों की भूमिका, लोक जैव विविधता पंजी (PBR) के अद्यतन, स्थानीय जैविक संसाधनों के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण तथा लाभ-प्रभाग (Benefit Sharing) राशि के नियमानुसार उपयोग एवं प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर उप वनमंडल अधिकारी पश्चिम कटनी श्री कार्तिकेय भट्ट, उप वनमंडल अधिकारी पूर्व कटनी श्री जगदीश वास्ये तथा कटनी पीबीआर नोडल अधिकारी श्री मोहनदास नागवानी ने भी समितियों के दायित्व, कार्यप्रणाली

तथा ग्राम स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में उपस्थित 117 जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों एवं सचिवों ने प्रशिक्षण में सक्रिय सहभागिता करते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा अपने क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण एवं लोक जैव विविधता पंजी के प्रभावी क्रियान्वयन का संकल्प लिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, स्थानीय जैविक संसाधनों के संरक्षण को सुदृढ़ करने तथा जनसहभागिता आधारित संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा।

पीएम स्वनिधि पखवाड़ा : पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ दिलाने विशेष अभियान निगमायुक्त तपस्या परिहार के निर्देश पर 15 अगस्त तक नगर निगम कटनी द्वारा मिशन मोड पर आयोजित होगा अभियान

नवल किशोर

कटनी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से नगर निगम कटनी द्वारा 15 अगस्त तक “पीएम स्वनिधि पखवाड़ा” विशेष अभियान चलाया जाएगा। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सिटी मिशन मैनेजर यश रजक को निर्देश दिए हैं कि अभियान को मिशन मोड में संचालित करते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए।

प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे योजना की जानकारी- निगमायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजना की जानकारी पहुंचाकर उन्हें आवेदन, ऋण स्वीकृति, डिजिटल भुगतान और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं से जोड़ने की कार्यवाही प्राथमिकता से की जाए।

वेंडिंग जोन एवं बाजार क्षेत्रों में आयोजित करे विशेष शिविर- उन्होंने सिटी मिशन मैनेजर श्री रजक को निर्देशित किया कि नगर के सभी

चिन्हित वेंडिंग जोन एवं बाजार क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं तथा नए पात्र पथ विक्रेताओं के आवेदन प्राप्त कर उनका शीघ्र परीक्षण एवं बैंकों को प्रेषण सुनिश्चित किया जाए। पूर्व में अस्वीकृत प्रकरणों की पुनः समीक्षा कर पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं।

लंबित ऋण प्रकरणों का कराए शीघ्र निराकरण- निगमायुक्त ने बैंक अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित ऋण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, हितग्राहियों को डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करने तथा योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी व्यापक स्तर पर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान, शिविरों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना से लाभान्वित किया जाए।

विभिन्न सुविधाओं एवं योजनाओं से जोड़ने होंगे प्रयास-नगर निगम द्वारा बताया गया कि अभियान अवधि के दौरान पात्र पथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृति, डिजिटल वित्तीय सेवाओं, यूपीआई आधारित लेन-देन, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य संबंधित सुविधाओं एवं योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। साथ ही बैंकों एवं नगर निगम के बीच सतत समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

मधुर वाणी: सफलता, संबंध और आध्यात्मिक उन्नति की आधारशिला

वेदों का संदेश “सत्यम् वदं, प्रियम् वदं” केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने की एक साधना है। सत्य बोलना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उसे प्रेम, विनम्रता और मधुरता के साथ व्यक्त करना। यही गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं और उसके संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जाए तो सफल व्यक्ति केवल अपनी योग्यता से ही नहीं, बल्कि अपने मधुर व्यवहार और संतुलित वाणी के कारण भी सम्मान प्राप्त करते हैं। व्यापार, सामाजिक जीवन, पारिवारिक संबंध या कार्यस्थल—हर जगह विनम्र संवाद विश्वास और सहयोग का वातावरण निर्मित करता है। इसके विपरीत, कठोर शब्द सत्य होने पर भी अक्सर दूरी और कटुता पैदा कर देते हैं।

अक्सर यह कहा जाता है कि “सत्य कड़वा होता है।” किंतु वेदों की शिक्षा इससे आगे बढ़कर हमें बताती है कि सत्य को प्रिय और मधुर रूप में प्रस्तुत करना ही वास्तविक विवेक है। कहा जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में चेहरे की सुंदरता का योगदान सीमित होता है, जबकि उसकी वाणी का प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं; वे प्रेरणा, उत्साह और परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वाणी को संयमित, सकारात्मक और मधुर बनाने का अभ्यास करना चाहिए। सहज योग के अनुसार मधुर वाणी का स्रोत केवल बाहरी प्रशिक्षण नहीं, बल्कि आंतरिक जागृति है। जब



व्यक्ति सहज ध्यान के माध्यम से अपने भीतर स्थित चेतना से जुड़ता है, तब उसके व्यक्तित्व में स्वाभाविक परिवर्तन आने लगते हैं। कुंडलिनी

शक्ति के जागरण के साथ शरीर के सूक्ष्म चक्र सक्रिय होते हैं। इनमें गले में स्थित विशुद्धि चक्र के जागृत होने से संवाद में संतुलन, मधुरता और

आत्मविश्वास का विकास होता है। 28 अप्रैल 1991 के एक प्रवचन में श्री माताजी ने कहा था आपको कैसे बात करनी चाहिए, आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, सब कुछ बदल जाएगा यदि आप वास्तव में इस तथ्य से अवगत हो जाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो विवेक का स्रोत है। विवेक में आप बहुत सी चीजें सीखेंगे। पहली है सहनशीलता - “यह सब ठीक है। हम इसे हल कर लेंगे। यह काम करेगा।” आप सीखेंगे कि वह प्रेम क्या है जो अलग है। आप सीखेंगे कि वह हास्य क्या है जो गुदगुदाता है, लेकिन चोट नहीं पहुँचाता है। आप यह भी सीखेंगे कि अपने व्याख्यानों में क्या कहना है, क्या सुनना है।

और सभी चीजों में से, आप यह जानेंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के दर्शन को कैसे पूरा किया जाए। आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में मधुर वाणी केवल एक सामाजिक गुण नहीं, बल्कि मानसिक शांति, स्वस्थ संबंधों और आध्यात्मिक विकास का सशक्त माध्यम है। यदि व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और संतुलन का विकास करे, तो उसके शब्द स्वयं ही मधुर बन जाते हैं और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सहज योग एक सरल एवं पूर्णतः निःशुल्क ध्यान पद्धति है। अपने निकटतम सहज योग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1800 2700 800 या वेबसाइट sahajayoga.org.in से प्राप्त कर सकते हैं।

बुरहानपुर से 55 श्रद्धालुओं का जत्था तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए रवाना; प्रशांत पाटिल की 20 वर्षों की अटूट यात्रा बनी प्रेरणा

महेन्द्र मालवीय
रणजीत टाइम्स

बुधवार बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला, जब 55 श्रद्धालुओं का एक जत्था भगवान श्री तिरुपति बालाजी के पावन दर्शन हेतु रवाना हुआ। स्टेशन पर श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए भगवान श्री बालाजी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस धार्मिक यात्रा की सबसे मुख्य विशेषता आदरणीय प्रशांत जी पाटिल की निरंतर सेवा और आस्था है। वे विगत 20 वर्षों से लगातार श्री तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं। भगवान के प्रति उनका अटूट समर्पण और गहरी आस्था क्षेत्र के अनेक श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है। प्रशांत जी पाटिल



के कुशल नेतृत्व में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन यात्रा से जुड़ते हैं और बालाजी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बालाजी महाराज के दर्शन

मात्र से ही मन को अपार शांति, असीम आनंद और सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है।

जत्थे में प्रमुख रूप से शामिल श्रद्धालु:

इस यात्रा में प्रशांत जी पाटिल के साथ धनराज जी महाजन, अशोक जी राठौड़, संजय जी शाह, किशोर जी असवार, हेमंत जी महाजन, शैलेश जी, राकेश मिश्रा, वरिष्ठ भाई साहब संजय जी होलकर, प्रकाश जी लॉर्ड, भीम सिंह चौहान, शैलेंद्र कपूर सहित अन्य गणमान्य एवं श्रद्धालु सम्मिलित हैं। रवाना होने से पूर्व सभी श्रद्धालुओं ने भगवान श्री तिरुपति बालाजी के चरणों में नमन कर संपूर्ण देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और समस्त नागरिकों के मंगलमय जीवन की कामना की।

18 साल से फरार 30 हजार का इनामी वारंटी गिरफ्तार

दिव्यानंद अर्गल

छतरपुर। जिला पुलिस द्वारा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ‘न्याय पथ अभियान’ के तहत लवकुशनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2008 के तीन अलग-अलग मामलों में पिछले 18 वर्षों से फरार चल रहे 30 हजार रुपये के इनामी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार आरोपी रामनरेश शुक्ला उर्फ मिल्लू, निवासी ग्राम मुंडेरी, थाना लवकुशनगर, गृहभेदन कर मारपीट, अपहरण और डकैती के तीन अलग-अलग प्रकरणों में फरार था। प्रत्येक मामले में 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन तथा



एसडीओपी लवकुशनगर नवीन दुबे के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय अंबे, उपनिरीक्षक ज्ञान सिंह, प्रधान आरक्षक ओमपाल सिंह, दीपक चतुर्वेदी तथा आरक्षक विकास सिंह, ब्रजेश अहिरवार और बलराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सिल्वर पार्क कॉलोनी में बिना पुलिस वेरिफिकेशन रह रहे उपद्रवियों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई

टीआई राजकुमार यादव के सख्त निर्देशों पर
धारा 135 व 126 के तहत दंडात्मक कार्रवाई

लसूड़िया थाना क्षेत्र | विशेष अपराध एवं
सुरक्षा समाचार

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिल्वर पार्क कॉलोनी में सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर बिना पुलिस वेरिफिकेशन (सत्यापन) के रह रहे उपद्रवियों ने आतंक मचा रखा था। रहवासियों को डराने-धमकाने, शराब पीकर हुड़दंग मचाने और बच्चों को अगवा करने की धमकी देने के इस मामले को थाना प्रभारी (TI) राजकुमार यादव ने बेहद गंभीरता से लिया। टीआई राजकुमार यादव के संज्ञान में आते ही उन्होंने तुरंत सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 135 और 126 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की है प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिल्वर पार्क फेस-2 में रहने वाली सपना वाडेकर ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि कॉलोनी में बिना वेरिफिकेशन के रह



रहे किराएदार और बाहरी लड़के लगातार आतंक फैला रहे हैं। घर के सामने बच्चों के खेलने के



दौरान आरोपियों ने न केवल अभद्रता और गंदी गालियां दीं, बल्कि खुद को ग्वालियर का बताकर

और आपराधिक प्रवृत्ति का रोब झाड़कर बच्चों को जान से मारने तथा किडनैप करने की धमकियां दीं।

पुलिस द्वारा की गई मुख्य कार्रवाई: मामले की गंभीरता और सुरक्षा में बड़ी चूक (बिना वेरिफिकेशन रहना) को देखते हुए पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए निम्नलिखित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

विपुल पिता किशन लाल, निवासी - सिल्वर पार्क, लसूड़िया, इंदौर

राधे श्याम पिता शोभाराम, निवासी - सिल्वर पार्क, लसूड़िया, इंदौर

इस घटना के बाद स्थानीय रहवासियों ने बिना सत्यापन मकान किराए पर देने वालों और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में बिना पुलिस वेरीफाइड किराएदारों को रखने वाले मकान मालिकों और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में आवासीय भवनों में कमर्शियल एक्टिविटी- कोर्ट में आज सुनवाई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहवासी, कहा- फोटो और वीडियो दिखाएंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में रेसीडेंसियल यानी, आवासीय भवनों के कमर्शियल उपयोग पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। अब सुनवाई बुधवार को होगी।

बता दें कि शहर के कई इलाकों में आवासीय प्रॉपर्टी पर सालों से कमर्शियल गतिविधियों की जा रही हैं। इसे लेकर अरेरा कॉलोनी सहित अनेक आवासीय क्षेत्र के रहवासी आवासीय भूखंडों पर हो रहे व्यावसायिक निर्माण एवं व्यवसायों के विरुद्ध शिकायत कर रहे थे। रहवासी पूर्णेंदु शुक्ला एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।

इधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्ती की है। ऐसे में निगम को कार्रवाई करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। दो दिन में कई प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया। कड़ियों ने निगम की कार्रवाई के बाद स्वेच्छा से दुकानें बंद कर दी थी। हालांकि, रविवार शाम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी। जिसमें फिलहाल व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया गया था। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। साथ ही मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश कौशलेंद्र विक्रम सिंह, भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, निगम कमिश्नर संस्कृति जैन भी



उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरे मामले की समीक्षा के लिए राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। यह समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अध्ययन कर पूरे प्रकरण की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समिति की रिपोर्ट आने तक व्यापारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सोमवार को अधिकांश दुकानें फिर से खुल गईं।

निगम ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की, प्रतिष्ठान पुनः खुलना भी गलत- अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी ने

बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने जिन अवैध दुकानों को सील करने का नोटिस जारी किया था, उनके विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है।

विधायक बोले-भोपाल का मास्टर प्लान लागू हो- इस मामले में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहा है। चूंकि, भोपाल में पिछले 20 साल से मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। इसमें व्यापारियों की क्या गलती है? सरकार जल्द ही मास्टर प्लान लागू करेगी। इसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं।

रहवासियों ने निकाली थी रैली

मुख्यमंत्री की मीटिंग से पहले रविवार को अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़ियाकलां समेत कई इलाकों में आवासीय परिसरों में कमर्शियल एक्टिविटी के विरोध में रहवासी सड़क पर उतरे थे। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के तत्वाधान में रहवासियों ने पैदल मार्च भी निकाला था। जिसमें लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी।

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी मोर्चा संभाला

इस मामले में भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) मैदान में उतरा है। संगठन ने व्यापारियों के हित में मिक्स लैंड यूज की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष गोविंद गोयल और सचिव अजय देवनानी ने बताया कि भोपाल विकास योजना (मास्टर प्लान) का अंतिम प्रकाशन वर्ष 2005 में हुआ था। इसके बाद नया मास्टर प्लान आज तक लागू नहीं हुआ है। इस वजह से शहर के अनेक क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के अनुरूप पर्याप्त कमर्शियल भूखंड उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ऐसी परिस्थितियों में 10 नंबर मार्केट, अरेरा कॉलोनी, 11-12 नंबर मार्केट, 1100 क्वार्टर्स, सहयोग विहार, बावड़ियाकलां, रोहित नगर सहित नए भोपाल के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर हजारों व्यापारी वर्षों से आवासीय भूखंडों से ही अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में अस्पताल, बैंक, क्लीनिक, शोरूम एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थान वर्षों से संचालित होकर नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी व्यवसायी नियमित रूप से नगर निगम को व्यावसायिक दर से संपत्ति कर, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को कमर्शियल दर से विद्युत शुल्क और शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त करों एवं शुल्कों का भुगतान कर रहे हैं। इससे शासन को करोड़ों रुपए का नियमित राजस्व प्राप्त हो रहा है।

आवासीय परिसर में व्यवसाय करना विवशता- चैंबर के सचिव देवनानी ने बताया कि व्यापारियों द्वारा आवासीय परिसरों में व्यवसाय संचालित करना उनकी विवशता है, क्योंकि नवीन मास्टर प्लान के अभाव में उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

अनिल अंबानी की
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर
की 179.66 करोड़ की
संपत्ति कुर्क, रिलायंस
पावर में हिस्सेदारी भी
आई दायरे में

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों के लिए एक और बड़ी कानूनी चुनौती सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 179.66 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस कार्रवाई की जानकारी कंपनी ने स्वयं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कंपनी के निवेशकों और शेयरधारकों के बीच हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि कुर्क की गई संपत्तियों में रिलायंस पावर लिमिटेड में कंपनी की हिस्सेदारी भी शामिल है, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, 3 अगस्त 2026 को उसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' (क्रमांक 36/2026) प्राप्त हुआ। यह आदेश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में जारी है।

5 देशों में राजनयिक मिशन बंद करेगा अमेरिका? जानिए क्या है इसकी रणनीति



वॉशिंगटन। अमेरिका पांच देशों में अपने कुछ दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को बंद करने की तैयारी कर रहा है। इस कदम को अमेरिकी विदेश नीति, संसाधनों के पुनर्गठन और वैश्विक प्राथमिकताओं में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन विदेशों में अपने राजनयिक नेटवर्क की समीक्षा कर रहा है। जिन मिशनों में गतिविधियां सीमित हैं या जहां परिचालन लागत अधिक है, वहां दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के पुनर्गठन अथवा बंद करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी राजनयिक मिशन को बंद करने का अर्थ संबंधित देश से संबंध समाप्त करना नहीं होता। ऐसे मामलों में दूतावास की जिम्मेदारियां अक्सर किसी पड़ोसी देश स्थित अमेरिकी मिशन या वैकल्पिक राजनयिक व्यवस्था के माध्यम से निभाई जाती हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय अमेरिकी प्रशासन की औपचारिक मंजूरी के बाद ही लागू होगा। इस कदम को वैश्विक कूटनीतिक रणनीति और प्रशासनिक खर्चों के पुनर्संयोजन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

न्याय मिला या सवाल टल गए?

दिल्ली के जंतर-मंतर से अदालत के फैसले तक तीन साल की यह कहानी सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह की नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था, खेल संस्थाओं, राजनीति और जनआंदोलनों की भी परीक्षा रही है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। अदालत का फैसला कानून की कसौटी पर अंतिम शब्द होता है और उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन इस फैसले के साथ कई ऐसे सवाल भी खड़े हैं, जिनका जवाब देश अब भी तलाश रहा है। जब देश के ओलंपिक और विश्व पदक विजेता खिलाड़ी सड़क पर बैठने को मजबूर हुए, तब खेल महासंघों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठे। यदि आरोप इतने कमजोर थे कि अदालत में टिक नहीं सके, तो तीन वर्षों तक देश को असमंजस में क्यों रखा गया? और यदि महिला खिलाड़ियों की शिकायतें वास्तविक थीं, तो जांच ऐसी क्यों हुई कि अदालत तक पहुंचते-पहुंचते मामला कमजोर पड़ गया? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान भारतीय कुश्ती की साख को हुआ। खिलाड़ी अखाड़े की बजाय धरनों और अदालतों में दिखाई दिए। खेल राजनीति



का अखाड़ा बन गया। विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ हथियार बनाया, सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया और अंत में सबसे पीछे छूट गया भारतीय खेल। यह मामला केवल एक व्यक्ति के बरी होने या आरोपमुक्त होने का नहीं है। यह जांच एजेंसियों की गुणवत्ता, खेल संघों की जवाबदेही और महिला खिलाड़ियों के भरोसे का भी मामला है। यदि शिकायतें झूठी थीं तो झूठे आरोप लगाने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि जांच में कमी रही तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लोकतंत्र में न तो मीडिया ट्रायल न्याय का विकल्प हो सकता है और न ही केवल आरोप किसी को अपराधी साबित कर सकते हैं। देश को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां महिला खिलाड़ी बिना भय शिकायत कर सकें, जांच निष्पक्ष और समयबद्ध हो तथा किसी भी मामले का राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर रहकर समाधान हो। तीन साल की इस लड़ाई ने यही सिखाया है कि न्याय में देरी केवल अदालतों की नहीं, संस्थाओं की विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन जाती है। अदालत का फैसला आ चुका है।

‘मातोश्री’ में बैठक के दौरान तीखी बहस, महिला नेता के इस्तीफे से ठाकरे गुट में बड़ी हलचल

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में संगठनात्मक बैठक के दौरान हुई तीखी बहस के बाद पार्टी की महिला जिला संगठन प्रमुख वैशाली दरेकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटनाक्रम ‘मातोश्री’ में आयोजित बैठक के बाद सामने आया, जिससे पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान पदाधिकारियों के बीच संगठनात्मक मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। इसके कुछ समय बाद वैशाली दरेकर ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि, पार्टी की ओर से इस्तीफे के कारणों पर अभी विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम ऐसे



समय सामने आया है, जब महाराष्ट्र की राजनीति में सभी दल आगामी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में संगठन के भीतर असंतोष या मतभेद की खबरें पार्टी के लिए चुनौती बन सकती हैं। अब सभी

की नजर इस बात पर है कि उद्धव ठाकरे इस मामले को किस तरह सुलझाते हैं और क्या पार्टी नेतृत्व इस्तीफे के बाद संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए कोई नया कदम उठाता है।

खाड़ी संकट के बीच ईरान में भारत की नई कूटनीतिक तैनाती, कौन हैं आईएफएस विश्वेश नेगी?

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा चिंताओं और भारत के रणनीतिक हितों के बीच केंद्र सरकार ने 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है।

वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और शीघ्र ही तेहरान में कार्यभार



संभालेंगे। विश्वेश नेगी अनुभवी करियर राजनयिक हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के साथ रक्षा मंत्रालय में भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मामलों पर काम किया है। हाल के वर्षों में वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े कूटनीतिक मामलों का भी नेतृत्व कर चुके हैं, जिससे उन्हें सामरिक और बहुपक्षीय कूटनीति का व्यापक अनुभव मिला है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब ईरान और पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति संवेदनशील बनी हुई

है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है और भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है। ऐसे में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की भूमिका ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत लगातार यह रुख दोहराता रहा है कि क्षेत्रीय तनाव का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव है।

खिलाड़ियों ने सरकार और सहयोगी संस्थाओं का जताया आभार

भारत लौटने पर भारतीय टीम का भव्य स्वागत

नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने वाली भारतीय टीम का दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, परिवार के सदस्य, खेल अधिकारी और समर्थक एयरपोर्ट पहुंचे। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और भारत माता के जयघोष के बीच खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। खिलाड़ियों ने इस सम्मान के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वागत उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है और आगे भी वे देश के लिए इसी तरह पदक जीतने का प्रयास करेंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के 96 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत ने मुक्केबाजी में सात स्वर्ण पदक जीते हैं। यह उपलब्धि न केवल भारतीय बॉक्सिंग के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

उन्होंने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सभी सहयोगी संस्थाओं को इस सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि अब भारतीय मुक्केबाजों की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत हुई है। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने एयरपोर्ट पर मिले शानदार स्वागत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इतने लोगों को स्वागत के लिए उपस्थित देखकर उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है।



साक्षी ने कहा कि भारत सरकार, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार ने हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया है। इसी सहयोग और बेहतर प्रशिक्षण के कारण यह सफलता संभव हो सकी। उन्होंने अपना स्वर्ण पदक देशवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे भारत की है और वे भविष्य में भी देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे।

साक्षी चौधरी के दादा सतपाल सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी पोती पर बेहद गर्व है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि यदि वे दृढ़

संकल्प और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं उनकी भाभी प्रिया ने कहा कि साक्षी की जीत पूरे परिवार के लिए भावुक कर देने वाला पल था। जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और सभी बेसब्री से उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी टीम के प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और देश लौटने पर मिले सम्मान ने उनकी खुशी को कई गुना बढ़ा दिया।

वेटलिफ्टिंग में पदक विजेताओं को खेल मंत्री मांडविया ने सम्मानित किया

सौंपे नकद पुरस्कार

नई दिल्ली। भारतीय वेटलिफ्टर्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 8 मेडल जीते, जिनमें 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहा। इसके साथ ही भारतीय दल ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। स्वदेश लौटने पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को इन पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार उपलब्धियों के लिए गोल्ड मेडल विजेताओं को 30 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेताओं को 20 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिए। वेटलिफ्टर्स को बधाई देते हुए मांडविया ने कहा कि पूरे देश ने उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया। उन्होंने कहा, 'संसद में भी, हर बार जब आपने पदक जीते, तो घोषणाएं की गईं। उन पलों ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया।' मनसुख मांडविया ने कोचों की जमकर तारीफ की, जिनमें द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता विजय शर्मा भी शामिल थे। उन्होंने चैंपियन बनाने में कोचों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा, 'एक एथलीट के सफर में गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। चैंपियन बनाने में कोच के योगदान से बड़ी कोई चीज नहीं है।' कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने लगातार तीन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनकर इतिहास रचा, जबकि ऋषिकांत सिंह और वल्लुरी अजय बाबू ने स्नैच में नए 'कॉमनवेल्थ गेम्स' रिकॉर्ड बनाए। ज्ञानेश्वरी यादव और हरजिंदर कौर सहित कई वेटलिफ्टर्स ने अपना पर्सनल-बेस्ट प्रदर्शन किया। इन खेलों में 11 वेटलिफ्टर्स में से छह 'खेलो इंडिया एथलीट' (केआईई) हैं।



गाली देना 'कूल' नहीं, मनु भाकर का युवाओं से बड़ा संदेश, बोलीं-

शब्द ही हैं आपकी पहचान

नई दिल्ली। आज सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और अपमानजनक भाषा को 'कूल' दिखाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में पेरिस ओलंपिक की दोहरी पदक विजेता मनु भाकर ने इस सोच को खुली चुनौती दी है। मनु भाकर का कहना है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से होती है और गाली देना कभी भी 'कूल' नहीं हो सकता।

मनु भाकर के मुताबिक, मेहनत, ईमानदारी, दूसरों के प्रति सम्मान और देश का नाम रोशन करना ही असली 'कूल' होने की निशानी है। मनु भाकर ने किसी खास घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन रोजाना की बातचीत में गाली-गलौज वाली भाषा के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में चिंता जाहिर की।

मनु भाकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर वीडियो में कहा, "दिल से निकली एक बात शेयर कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जिन लोगों का ध्यान जल्दी भटक जाता है, जो बेसब्र हैं या जिन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है, उन्हें यह वीडियो थोड़ा लंबा लग सकता है। फिर भी अगर आप 2-3 मिनट निकाल पाएँ तो



मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुले मन से मेरी बात सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे।"

मनु भाकर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "अगर आपका नजरिया अलग है या आप कुछ और कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आपकी बातें जानकर बहुत खुशी होगी। अच्छी चर्चा और अलग-अलग विचारों का हमेशा स्वागत है।"

मनु भाकर ने कहा, "इंसान की भाषा उसके व्यक्तित्व का आईना होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि समय के साथ इंसान वही बनता है, जैसा वह सोचता है, बोलता है और अपने जीवन में अपनाता है। खराब भाषा या गाली-गलौज करना किसी भी तरह से 'कूल' नहीं है।" मनु भाकर ने लिखा, "बुरी भाषा का इस्तेमाल करना 'कूल' नहीं है। गाली-गलौज करना 'कूल' नहीं है। आइए 'कूल' की परिभाषा को आसान तरीके से समझते हैं। मेहनती होना, दयालु होना, दूसरों और खुद के प्रति सम्मान रखना, ईमानदारी से सफल होने की कोशिश करना और अपने माता-पिता और देश का

संरक्षण करना। FSSAI की जांच में पाया गया कि कई उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार सामग्री में "100% प्योर", "100% नेचुरल" और इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, जबकि ऐसे दावों के समर्थन में आवश्यक वैज्ञानिक और नियामकीय आधार उपलब्ध नहीं था। इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का

विमेन एकेडमी चैंपियनशिप: एमपी हॉकी एकेडमी का डबल धमाल

सब-जूनियर और जूनियर कैटेगरी में जीता खिताब

नई दिल्ली। ग्वालियर चौथी हॉकी इंडिया विमेन एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन ए और बी) में सोमवार को मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के लिए यादगार दिन रहा, जिसने सब-जूनियर और जूनियर दोनों कैटेगरी में खिताब अपने नाम किए। ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित प्रतियोगिता के सब-जूनियर महिला फाइनल में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने एक रोमांचक मुकाबले के बाद प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी, सोनीपत को 2-2 (3-1 शूटआउट) से हराया।

प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने मुकाबले के छठे मिनट में कप्तान दीपा के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन 9वें मिनट में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के लिए गीताश्री नम्मी ने बराबरी का गोल दागा। 44वें मिनट में गुंजन ने प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी को फिर से बढ़त दिलाई, लेकिन जागृति यादव ने 55वें मिनट में गोल करके मुकाबले को शूटआउट तक पहुंचा दिया। शूटआउट में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के लिए

भाविका, सरोज मानसी और गीताश्री नम्मी ने सफल प्रयास किए, जबकि गोलकीपर परिधि मेवाड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया और उनकी टीम ने 3-1 से शूटआउट जीतकर खिताब अपने नाम किया। इससे



पहले, राजा करण हॉकी एकेडमी ने चीमा हॉकी एकेडमी पर 4-3 की रोमांचक जीत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। तन्वी ने 23वें और 36वें मिनट में दो गोल किए, जबकि 31वें मिनट में रिया और 33वें मिनट में दीक्षा ने भी गोल किए।

अब पैकेट पर नहीं चलेगा '100% प्योर' का खेल! FSSAI के रडार पर डाबर, जारी किया कड़ा आदेश

नई दिल्ली। खाद्य उत्पादों पर आकर्षक दावों के जरिए ग्राहकों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति पर अब सख्ती शुरू हो गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 3 अगस्त को डाबर इंडिया के कई लोकप्रिय उत्पादों पर "100%" शब्द का इस्तेमाल भ्रामक मानते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी

किया है। FSSAI की जांच में पाया गया कि कई उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार सामग्री में "100% प्योर", "100% नेचुरल" और इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, जबकि ऐसे दावों के समर्थन में आवश्यक वैज्ञानिक और नियामकीय आधार उपलब्ध नहीं था। इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का

उल्लंघन माना गया।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि कोई भी खाद्य कंपनी बिना पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण और नियामकीय अनुमति के उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले दावे नहीं कर सकती। ऐसे दावों से ग्राहकों के खरीद निर्णय प्रभावित होते हैं, इसलिए इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने

कंपनी को संबंधित पैकेजिंग, लेबल और प्रचार सामग्री से "100%" जैसे दावे हटाने तथा नियमों के अनुरूप संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो आगे नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं मानी जा रही है।

सरचार्ज माफ होने पर भी क्यों पानी का बिल नहीं भर रहे दिल्ली वाले सिर्फ 32% उपभोक्ताओं ने उठाया छूट का लाभ

नई दिल्ली, एजेंसी। पानी के गलत बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) माफी योजना की घोषणा की थी। 31 जनवरी को समाप्त होने वाली इस योजना की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी, इसके बाद भी उपभोक्ता इसका लाभ उठाने में संकोच कर रहे हैं। इसका मूल कारण उपभोक्ताओं को भेजा गया भारी भरकम बिल है। जुर्माना व सरचार्ज माफ करने के बाद भी पानी बिल की राशि अधिक है। इसे ठीक कराने के लिए वह जल बोर्ड के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

15 अगस्त को समाप्त होगी योजना

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के आंकड़ों के अनुसार एलपीएससी माफी योजना का लाभ बकाया राशि वाले केवल 32.6 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही उठाया है,

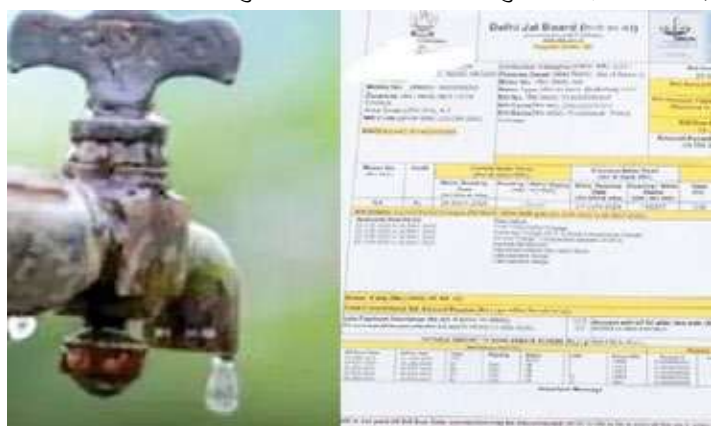
जबकि यह योजना 15 अगस्त को समाप्त होने वाली है।

कब शुरू की गई थी योजना

14 अक्टूबर, 2025 को जब यह योजना शुरू की गई थी, तब लगभग 14.6 लाख लोगों के बिल बकाया थे, जिनमें से केवल 4,78,999 (32.6 प्रतिशत) लोगों ने ही छूट का लाभ उठाया है। 67.38 प्रतिशत लोगों का बकाया अभी भी बाकी है। जल बोर्ड बिल संबंधित मामलों के समाधान के लिए जोनल रेवेन्यू ऑफिसर स्तर पर समिति बनाने का निर्णय लिया है।

इस योजना का उद्देश्य इन बकाया राशियों के भुगतान को आसान बनाना है, जिसके तहत उपभोक्ता को केवल मूल राशि का भुगतान करना है। सरकार ने ब्याज और लेट पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया है। योजना शुरू होने के बाद से डीजेबी ने 641.11 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है, जबकि उपभोक्ताओं के 1,709.72 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज माफ किए गए हैं।

उपभोक्ताओं पर 87,588 करोड़ रुपये था बकाया योजना शुरू होने के 7,125 करोड़ रुपये थी और एलपीएससी शुल्क 80,463 करोड़



समय घरेलू, सरकारी और व्यावसायिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 87,588 करोड़ रुपये से अधिक का बिल बकाया था। इसमें से मूल बिल बकाया राशि

रुपये था। घरेलू श्रेणी में, लंबित बिल 16,126 करोड़ रुपये के थे, जिसमें 5,057 करोड़ रुपये मूल राशि के रूप में और 11,069 करोड़ रुपये एलपीएससी

के रूप में थे।

योजना की अवधि बढ़ाए जाने के बाद भी बिल भुगतान की गति काफी धीमी है। दिल्ली सरकार ने 30 जनवरी को घोषणा की थी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में योजना को 15 अगस्त तक बढ़ाया जा रहा है।

सरकार ने बताया था कि तब तक, 3.3 लाख उपभोक्ताओं (लगभग 22 प्रतिशत) ने इस योजना का लाभ उठाया था और 29 जनवरी तक 430 करोड़ रुपये का मूल बकाया बिल का भुगतान हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि जल बोर्ड ने बकाया बिलों के निपटान के लिए ऑनलाइन और एप-आधारित भुगतान सुविधाएं शुरू की हैं। अधिकारी ने आगे कहा अधिकांश उपभोक्ताओं का तर्क है कि उनके बिल शून्य हुआ करते थे या कभी जनरेट ही नहीं होते थे, लेकिन उन्हें अचानक भारी-भरकम बिल भेज दिए गए हैं।

दिल्ली में यातायात नियम तोड़ने वालों की होगी काउंसिलिंग, 872 ट्रैफिक पाठशालाओं में 17420 चालकों को किया जागरूक

नई दिल्ली, एजेंसी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सिर्फ चालान की कार्रवाई करने के बजाय अब उन्हें उनकी गलती और उससे होने वाले खतरे के बारे में भी समझाया जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और वाहन चालकों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सभी ट्रैफिक सर्किलों में ट्रैफिक पाठशाला शुरू की है। अब तक पूरी दिल्ली में 872 ट्रैफिक पाठशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इनमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 17,420 वाहन चालकों की काउंसिलिंग और उन्हें जागरूक करने के साथ चालान भी किया गया है।

यातायात पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर शिक्षा, प्रवर्तन और प्रोत्साहन की त्रि-लेयर स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। ट्रैफिक पाठशाला इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है।

सभी ट्रैफिक सर्किलों के अलावा प्रमुख चौराहों, ज्यादा भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों और शिक्षा संस्थानों तक भी इस कैंपेन को पहुंचाया जा रहा है।

ट्रैफिक पाठशाला में खासतौर पर बाइक पर ट्रिपल



राइडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, रेड लाइट जॉपिंग, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने, ड्रंकन ड्राइविंग और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल जैसे यातायात उल्लंघन पर वाहन चालकों की काउंसिलिंग की जा रही है।

नियम पालन पर कार्रवाई भी, पुरस्कार भी इसके अलावा पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चालान करने के साथ

वाहन चालक को यह भी समझाया जा रहा है कि ट्रैफिक नियम सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी हैं। वहीं, ट्रैफिक नियम का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अब तक जिम्मेदारी से वाहन चलाने और ट्रैफिक नियम का पालन करने वाले 2,535 लोगों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने किया गोपबन्धु दास की प्रतिमा का अनावरण, लोकसेवा और राष्ट्रभक्ति के योगदान को किया याद

नई दिल्ली, एजेंसी। लाजपत नगर स्थित लाजपत भवन में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष रहे उत्कलमणि गोपबन्धु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पूर्व उन्होंने लोकसेवक मंडल के संस्थापक व महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। गोपबन्धु दास ओडिशा के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार थे, जिनका जीवन लोकसेवा, राष्ट्रभक्ति और मानवता की प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। राजधानी दिल्ली में उनकी पहली प्रतिमा स्थापित की गई। कांस्य की यह प्रतिमा 75 किलोग्राम वजन वजनी है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लोकसेवक मंडल के आजीवन सदस्यों व पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और कुशलक्षेम जाना। संस्था के मुताबिक उत्कलमणि गोपबन्धु दास ने गरीबों, किसानों, अनाथों और पीड़ितों की सेवा को अपना जीवन समर्पित किया। लाला लाजपत राय के आग्रह पर लोकसेवक मंडल से जुड़े। शिक्षा के प्रसार के लिए सत्यवादी विद्यालय की स्थापना की और पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई। निस्वार्थ सेवा, त्याग और जनकल्याण के कारण उन्हें उत्कलमणि यानी ओडिशा का रत्न की उपाधि मिली। गोपबन्धु दास के आदर्शों का अनुसरण करने का लिया संकल्प उनका जीवन लोकसेवा, राष्ट्रभक्ति और मानवता की प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। उनके उराष्ट्रसेवा, शिक्षा, सामाजिक समर्पण एवं लोक-कल्याण के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने व नई पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाजपत भवन में उनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है।

ट्रंप की नई टैरिफ नीति के खिलाफ 25 राज्य

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर चर्चा में है। 25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का आरोप है कि ये नए टैरिफ फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आयात करों को बदलने का बहाना हैं। पिछले महीने यानी जुलाई में अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंक वाले टैरिफ लगाए थे। ये टैरिफ जबर्न श्रम से उत्पादित आयात पर पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप में लगाए गए। नए टैरिफ तब प्रभावी हुए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अस्थायी टैरिफ की समय सीमा समाप्त हो गई। सोमवार को (अमेरिकी समय) 25 राज्यों की तरफ से किए गए मुकदमे के संबंध में न्यूयॉर्क की अदालतों जनरल लैटिटिया जेम्स ने कहा कि प्रशासन अवैध रूप से परिवारों और व्यवसायों पर कर बढ़ा रहा है। ट्रंप का तर्क है कि उच्च टैरिफ अमेरिकी विनिर्माण को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का हवाला दिया था। उन्होंने व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ लगाए थे। लेकिन

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि टैरिफ को अधिकृत नहीं करता। इस फैसले के बाद प्रशासन को टैरिफ का भुगतान करने वाले आयातकों को वापसी भेजनी पड़ी। राजस्व की भरपाई के लिए ट्रंप ने अस्थायी 10 फीसदी वैश्विक टैरिफ लगाए, जो 24 जुलाई को समाप्त हो गए। अब ट्रंप 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत अधिक स्थायी टैरिफ लगा रहे हैं। यह धारा राष्ट्रपति को अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल देशों के खिलाफ आयात कर लगाने की अनुमति देती है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का इस्तेमाल किया था। वे अदालती चुनौतियों में भी टिके रहे थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका अपने वैध अधिकार का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जबर्न श्रम वाले सामान के आयात पर प्रतिबंध लागू न करना अनुचित है और अमेरिकी कारोबार पर बोझ डालता है।

आतंक के आकाओं में भरा खौफ

30 से ज्यादा आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने किया ढेर, लश्कर कमांडर ने खुद कबूला

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े एक वरिष्ठ आतंकी ने दावा किया है कि पिछले तीन से चार वर्षों में 30 से ज्यादा लश्कर आतंकियों का धुरंधर स्टाइल में हत्या की गई। लश्कर के आतंकी रिजवान हनीफ ने इन हत्याओं के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ होने का फर्जी दावा किया। उसने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत सरकार पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज कर चुकी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख और वरिष्ठ कमांडर रिजवान हनीफ यह दावा करता दिख रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 'अज्ञात हमलावरों' की मदद से लश्कर के कई आतंकियों की हत्या कराई।

हनीफ के मुताबिक, ये घटनाएं कराची, पेशावर, रावलपिंडी और पीओके के मुजफ्फराबाद तथा रावलकोट में हुईं। आतंकी भती और सीमा पार घुसपैठ में भूमिका के लिए कुख्यात रिजवान हनीफ वीडियो में हनीफ हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक और घृणा फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता भी सुनाई देता है।

पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे गए प्रमुख लश्कर आतंकियों में अबू सैफुल्लाह



उर्फ रजाउल्लाह निजामानी का नाम भी शामिल है। वह वर्ष 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय पर हुए हमले का आरोपी था। उसकी सिंध में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

यह दावा ऐसे समय सामने आया है, जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विरोध प्रदर्शन जारी है। हनीफ ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। भारत सरकार पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज करती रही है। हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि कुलगाम में दो पुलिसकर्मियों की हत्या की साजिश लश्कर कमांडर लतीफ भट और उसके सहयोगी वारिस शाह ने रची थी। जुलाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहलगाम आतंकी

हमले के मामले में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को आरोपी बनाया था। लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना 1980 के दशक के आखिर में पाकिस्तान में हाफिज मोहम्मद सईद, जफर इकबाल और अब्दुल्ला अज्जाम ने की थी।

यह संगठन 'मरकज-उद-दावा-व-अल-इरशाद' का उग्रवादी विंग था, जिसकी स्थापना सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान हुई थी। सोवियत सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद संगठन ने अपना ध्यान जम्मू-कश्मीर पर केंद्रित कर दिया। भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। भारत और कई पश्चिमी देशों का लंबे समय से आरोप रहा है कि इस संगठन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन प्राप्त है।